Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अगस्त (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन 51.52 करोड़ रुपए अंतरित किये 3
- मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सी.एम. डैश बोर्ड' का शुभारंभ किया 3
- मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की 4
- उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत सिर्फ 629 यूनिट 4
- काशी की प्रिया सिंह ने श्रीराम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग कर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया 5
- आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिये इकाना स्टेडियम की पिच को आईसीसी और बीसीसीआई की हरी झंडी 7
- उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2023 का प्रतिवेदन विधानसभा में पेश 8
- उत्तर प्रदेश सरकार ने किया जेल में बंद बंदियों और सिद्धदोष कैदियों का भत्ता दोगुना 10
- गढ़वा घाट पर बनेगा बनारस का पहला रिवर फ्रंट 10
- उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पेश किये चार विधेयक 12
- स्वास्थ्य सेवाओं में ई-गवर्नेंस के लिये उत्तर प्रदेश को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार 13
- लखनऊ में बनेगा एक नया आईटी हब 13
- उत्तर प्रदेश की नौ धरोहरों को मिलेगा हेरिटेज होटल का लुक 14
- आगरा में इनर रिंग रोड के किनारे बनेगा विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर 19
- उत्तर प्रदेश के 89 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक 19
- उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लांच किया गया 20
- चार दिवसीय वाई-20 (यूथ सम्मेलन) की वराणसी में हुई शुरुआत 20
- उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों में खोले जाएंगे दीदी कैफे 21
- उत्तर प्रदेश सरकार, कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को भी देगी मुफ्त किताबें 22
- उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त को पहली बार शाम को खुलेंगे स्कूल 23
- उच्च शिक्षा में भी 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' को मंज़ूरी 24
- गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ी हुए सम्मानित 25
- उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2023 26
- भारत की अध्यक्षता में जी20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न 27
- मुख्यमंत्री ने किया ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण 29
- सीकरी की वर्षा को मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 30

नोट :

उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन 51.52 करोड़ रुपए अंतरित किये

चर्चा में क्यों ?

31 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 5,100 लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन 51.52 करोड़ रुपए अंतरित किये।

प्रमुख बिंदु

- इसमें प्रथम किश्त के 250 लाभार्थी, द्वितीय किश्त के 2,602 लाभार्थी तथा तृतीय किश्त के 2,248 लाभार्थी सम्मिलित हैं।
- इस अवसर पर उन्होंने योजना के 12 लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाभी भी प्रदान की।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गोरखपुर जनपद में 42,600 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराये हैं।
- इसमें से 35,500 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और वहाँ पर लाभार्थी अपने घरों में रह रहे हैं।
- विगत 06 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी 61,184 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराये गए हैं।
- इस प्रकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 01 लाख 4 हज़ार लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सी.एम. डैश बोर्ड' का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

30 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), लखनऊ में 'मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सी.एम. डैश बोर्ड' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिन्दु

- मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सी.एम. डैश बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य डाटा कैप्चर करना तथा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के लिये शुरू हुए प्रयासों में गति लाना है। साथ ही आम जनमानस की संतुष्टि को भी इससे जोड़ना है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिये तकनीक का प्रयोग करना है। इससे प्रत्येक जनपद की हर एक गतिविधि को मॉनिटर कर सकते हैं।
- ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सी.एम. डैशबोर्ड का उपयोग विभिन्न विभागों में सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण सर्वोच्च स्तर से किये जाने हेतु किया जाएगा।
- सरकार की समस्त परियोजनाओं में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु एक इंटीग्रेटेड पोर्टल के रूप में सी.एम. डैशबोर्ड की स्थापना की गई है, इसके माध्यम से डाटा आधारित गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण प्रणाली का विकास किया गया है।
- सी.एम. डैशबोर्ड पर 53 विभागों के कुल 588 प्रोजेक्ट इंटीग्रेट किये जा चुके हैं। प्रदेश के सभी 93 विभागों को चरणबद्ध रूप से इस डैश बोर्ड से जोड़ा जाएगा।
- मुख्य सचिव द्वारा इनकी पाक्षिक समीक्षा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी।
- इसी से जनपदों तथा फील्ड में तैनात अधिकारियों की ग्रेडिंग भी तय हो सकेगी और इससे यह भी पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों तथा उनकी प्रगति के संबंध में डाटा कलेक्शन न होने के कारण प्रदेश में हुए विकास कार्यों की सही जानकारी नहीं हो पा रही थी। इसलिये सरकार ने इस संबंध में सही डाटा कैप्चर करने की शुरुआत की, जिससे प्रदेश की सही और अच्छी स्थिति सामने आ सकेगी।

मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2023 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की और व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रयागराज कुंभ से पूर्व प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता व नागरिक सुविधाओं में विस्तार के साथ ही प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता को 300 यात्रियों से बढ़ाकर 500 यात्री करने के निर्देश दिए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर हो, इसके लिये वहाँ पर आर.आर.टी.एस. या लाइट मेट्रो की व्यवस्था की जाए।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 17 हवाई पट्टियाँ हैं। जिनमे 08 हवाई पट्टियाँ भारतीय वायु सेना के अंतर्गत हैं।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2016-2017 में उत्तर प्रदेश में माल ढुलाई, जहाँ 5895 मीट्रिक टन थी, वहीं वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 20, 813 मीट्रिक टन हो गई। वर्ष 2016-2017 में प्रदेश में एयर ट्रैफिक जहाँ 46,585 था, वहीं वर्ष 2022-2023 में यह संख्या बढ़कर 82,615 हो गई है।
- हवाई उड़ानों के साथ-साथ यात्रियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-2017 में 59.97 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की है, वहीं 2022-2023 में 96.02 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा का लाभ उठाया है।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत सिर्फ 629 यूनिट

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बहुत कम 629 यूनिट प्रतिवर्ष है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सबसे कम खपत के मामले में बिहार ही उत्तर प्रदेश के बाद है, जबकि पूरे भारत का प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत औसत 1208 यूनिट प्रतिवर्ष है।
- उत्तर प्रदेश के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 629 यूनिट प्रतिवर्ष थी, जो वर्ष 2018-19 में घटकर 606 हो गई। वर्ष 2019-20 में यह 629 यूनिट प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पहुँच गई। इसके बाद की स्थिति के बारे में अभी घोषणा नहीं की गई है।
- प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़ाने के लिये रोस्टर का दौर धीरे-धीरे समाप्त होगा, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के प्रयास किये जाएंगे।
- इस संबंध में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कई राज्यों में रोस्टर प्रणाली लागू ही नहीं है। यही वजह है कि वहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष ऊर्जा खपत अधिक है।

कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत (वर्ष 2019-20)

राज्य	प्रति व्यक्ति खपत
गुजरात	2388 यूनिट
हरियाणा	2229 यूनिट
पंजाब	2171 यूनिट
छत्तीसगढ़	2044 यूनिट
दिल्ली	1572 यूनिट
हिमाचल प्रदेश	1527 यूनिट
महाराष्ट्र	1418 यूनिट
राजस्थान	1317 यूनिट
मध्य प्रदेश	1086 यूनिट
उत्तर प्रदेश	629 यूनिट
बिहार	332 यूनिट
देश में औसत	1208 यूनिट

काशी की प्रिया सिंह ने श्रीराम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग कर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार काशी की बीएफए फाइनल ईयर की छात्रा प्रिया सिंह ने श्रीराम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग कर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है। प्रिया ने यह पेंटिंग दो हज़ार 726 कील के ज़रिये प्लाइबोर्ड पर 26 घंटों में बनाकर विश्व में नया कीर्तिमान बनाया है।

प्रमुख बिंदु

- पांडेयपुर स्थित बीआर फांउडेशन परिसर में अपर ज़िला जज राकेश पांडेय ने पेंटिंग का उद्घाटन किया। जज राकेश पांडेय ने कहा कि इस पेंटिंग में भगवान श्रीराम के जीवन की प्रेरक कथाएँ छुपी हैं।
- वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड दुनिया के बड़े रिकॉर्ड में शुमार है। ज़िले के पुरंदरपुर गाँव की प्रिया सिंह इसे पाने में सफल हुई हैं। उन्होंने पेंटिंग का हुनर चित्रकार पूनम राय से सीखा है। उनकी प्रेरणा से उन्होंने अयोध्या के श्रीराम मंदिर की विशालकाय पेंटिंग तैयार की है।

नोट :

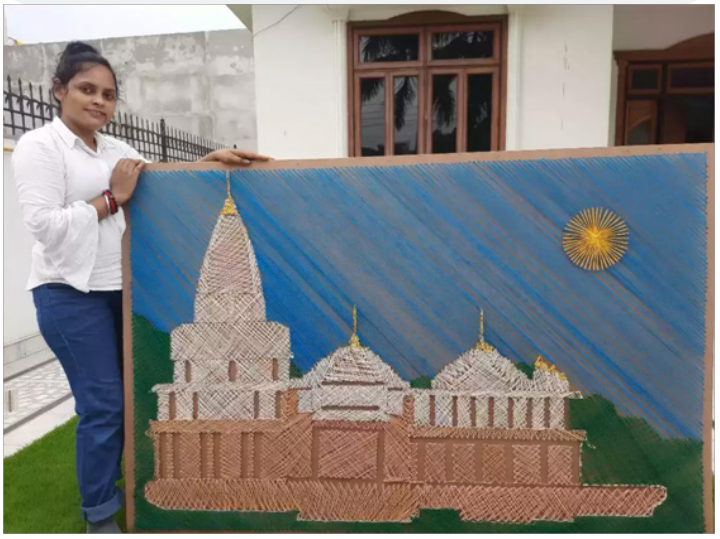

नोट :

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिये इकाना स्टेडियम की पिच को आईसीसी और बीसीसीआई की हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

5 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिये लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच को आईसीसी और बीसीसीआई की टीम ने हरी झंडी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की टीम ने इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) का निरीक्षण किया था। इस टीम ने सभी नौ पिच, आउट फील्ड सहित अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली थी।
- क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ का 5 अक्तूबर से आगाज़ हो जाएगा। इस महाकुंभ का ओपनिंग मैच पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और रनरअप रही न्यूज़ीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा।
- लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 के 5 मुकाबले खेले जाएंगे। ऐसा पहली बार है, जब लखनऊ क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। इकाना स्टेडियम में टूर्नामेंट का पहला मैच 13 अक्तूबर को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा।
- आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के पाँच मुकाबलों के बाद लखनऊ को सीनियर महिला इंटर जोनल 20-20 और महिला अंडर-23 एकदिवसीय क्रिकेट ट्रॉफी के 37 मैचों की मेजबानी का मौका मिला है। ये सभी मुकाबले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। लखनऊ के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब वह इतनी बड़ी संख्या में क्रिकेट मुकाबलों की मेज़बानी करेगा।

नोट :

उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2023 का प्रतिवेदन विधानसभा में पेश

चर्चा में क्यों ?

7 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2023 का प्रतिवेदन विधानसभा में पेश किया गया। 8 अगस्त तक इस पर विधायक संशोधन प्रस्ताव दे सकेंगे तथा 9 अगस्त को नियमावली पर सदन में चर्चा कर मंज़ूरी दिलाने की योजना है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2023 में ई-विधान के तहत सदन की कार्यवाही को अधिक-से-अधिक ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है।
- मंज़ूरी के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र नई नियमावली के तहत संचालित होगा। विधायकों के सवालों के जवाब सहित अन्य सूचनाएँ संबंधित विभाग से ऑनलाइन ली जा सकेंगी और ऑनलाइन ही विधायकों को दी जाएंगी।
- नियमावली में सदन में विधायकों के आचरण व व्यवहार तय किये गए हैं-
  - विधायक सदन में किसी दस्तावेज़ को फाड़ नहीं सकेंगे।
  - भाषण करते समय दीर्घा में किसी अजनबी की ओर संकेत नहीं करेंगे, न ही उसकी प्रशंसा कर सकेंगे।
  - विधायक अध्यक्ष की ओर पीठ करके न तो खड़े हो सकेंगे और न ही बैठ सकेंगे।
  - सदन में न शस्त्र ला सकेंगे, न ही प्रदर्शित कर सकेंगे।
  - ऐसे किसी भी साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिका, प्रेस टिप्पणी, पर्चों का वितरण नहीं कर सकेंगे, जो सदन से संबंधित न हों।
  - धूम्रपान नहीं कर सकेंगे।
  - लॉबी में इतनी तेज़ आवाज़ न तो बात करेंगे न ही हँसेंगे, जो सदन में सुनाई दे।
- विधानसभा का सत्र अब सात दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा-
  - वर्तमान में 15 दिन के नोटिस पर यह व्यवस्था है। शासन की ओर से विधानसभा सचिवालय को सत्र आहूत करने की तिथि से सात दिन पहले सूचना देनी होगी।
  - विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से प्रत्येक दिन के कार्य की सूची बनाकर उसकी एक प्रति विधायकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध करानी होगी।

नोट :

- विधानसभा अध्यक्ष, नेता सदन या सदन की अनुमति से कार्य के क्रम में परिवर्तन कर सकेंगे।
- विधायकों को ईमेल व मोबाइल संदेश के ज़रिये भी सत्र आहूत होने की सूचना दी जाएगी।

- अधिकारियों के नाम लेने पर रोक-
  - विधायक उच्च प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के आचरण पर तब तक आरोप नहीं लगा सकेंगे, जब तक कि चर्चा उचित रूप से रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।
  - सदस्य अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्य में बाधा डालने के लिये नहीं कर सकेंगे। सरकारी अधिकारियों के नाम को लेकर कोई उल्लेख नहीं करेंगे।
  - वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से राज्य के नाम का उपयोग नहीं करेंगे।
  - अध्यक्ष या पीठ की अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ सकेंगे। किसी भी दीर्घा में बैठे अजनबी के लिये निर्देश नहीं दे सकेंगे।
- नियमानुसार विधानसभा की नई नियमावली पर सदन में 14 दिन चर्चा होनी चाहिये, लेकिन सत्र केवल पाँच दिन का होने के कारण नियमावली पर शुक्रवार तक ही चर्चा हो सकेगी।
- भर्त्सना पर रुकेगी वेतन वृद्धि
  - नियमावली में विशेषाधिकार हनन के मामलों में भर्त्सना व जुर्माने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को देना प्रस्तावित है।
  - विधानसभा के प्रश्नों का जवाब नहीं देने या आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष भर्त्सना कर सकेंगे या उन पर जुर्माना भी लगा सकेंगे।
  - किसी अधिकारी या कर्मचारी की भर्त्सना करने या उन पर जुर्माना लगाने से उनकी वेतनवृद्धि और पदोन्नति प्रभावित होगी।
- तारांकित प्रश्न पर अधिकतम दो पूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे-
  - विधानसभा में अब किसी भी तारांकित प्रश्न पर दो पूरक प्रश्न ही पूछे जा सकेंगे। पूरक प्रश्न पूछने में पहली प्राथमिकता मूल प्रश्नकर्त्ता विधायक को मिलेगी। यदि प्रश्नकर्त्ता एक-से-अधिक हैं तो दूसरी प्राथमिकता दूसरे प्रश्नकर्त्ता को मिलेगी।
  - विधायक को अपने प्रश्न सत्र शुरू होने से तीन दिन पहले लिखित या ऑनलाइन विधानसभा के प्रमुख सचिव के समक्ष देने होंगे। सचिव को उन पर 24 घंटे के भीतर अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर उसी दिन सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
  - जनहित से जुड़े विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये सदस्यों को सदन की कार्यवाही शुरू होने से एक घंटे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन सूचना दो प्रति में विधानसभा के प्रमुख सचिव को देनी होगी।
  - ध्यान आकर्षण से संबंधित सूचना शासन की ओर से अधिकतम 30 दिन में संबंधित सदस्य या विधानसभा सचिवालय में पेश करनी होगी।

नोट :

उत्तर प्रदेश सरकार ने किया जेल में बंद बंदियों और सिद्धदोष कैदियों का भत्ता दोगुना

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के संयुक्त सचिव शिवगोपाल सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने जेलों में बंदियों व सिद्धदोष कैदियों का श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के कारागार में निरुद्ध कुशल, अर्धकुशल और अकुशल बंदियों को अभी 40 रुपए, 30 रुपए और 25 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। कैबिनेट ने अब यह राशि 81 रुपए, 60 रुपए और 50 रुपए कर दी है।
- वर्ष 2011 के बाद अब यह राशि महँगाई को देखते हुए बढ़ाई गई है।
- सिद्धदोष बंदी की स्थिति में पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत पीड़ित प्रतिकर कटौती पूर्व की भाँति की जाती रहेगी।
- यह दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
- यह पारिश्रमिक की दरें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 27 सितंबर, 2022 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लागू की गई हैं।

गढ़वा घाट पर बनेगा बनारस का पहला रिवर फ्रंट

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के उप निदेशक आर.के. रावत ने बताया कि बड़े महानगरों की तर्ज़ पर प्रदेश के बनारस में भी रिवर फ्रंट बनाने की योजना है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे बनारस में पर्यटन के अध्याय में एक और कड़ी जुड़ेगी।

प्रमुख बिंदु

- बनारस में हाइवे से सटे गंगा किनारे गढ़वा घाट पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। नमो घाट की तरह इस घाट को भी सजाया सँवारा जाएगा और इसे पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। यह रिवर फ्रंट पर्यटन को और ऊँचाइयों पर ले जाएगा।
- इस योजना का प्रस्ताव पर्यटन विभाग ने शासन को भेज दिया है। करीब नौ करोड़ रुपए की लागत से गढ़वा घाट को रिवर फ्रंट का रूप दिया जाएगा।

नोट :

- विदित है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से पर्यटकों का आकर्षण वाराणसी की ओर बढ़ा है। घाटों से अविरल निर्मल गंगा को निहारने और नौका विहार से लेकर शहर के अन्य पर्यटन स्थलों से रूबरू होने वाले पर्यटकों की संख्या में दिनों-दिन इजाफा हो रहा है। ऐसे में पर्यटन विभाग इस शहर को पर्यटन के लिहाज से और विकसित कर रहा है।
- गढ़वा घाट में फूड कोर्ट, किड्स ज़ोन, पार्किंग, आकर्षक टेबल व कुर्सियाँ, हरियाली के तहत ग्रीन गार्डेन, शेड, सेल्फी पॉइंट आदि सभी सुविधाएँ यहाँ पर्यटकों को मिलेंगी।
- अधिकारियों के अनुसार शहर के एक छोर पर स्थित गढ़वा घाट आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ हर किसी की पहुँच सुलभ और आसान होगी। शहर के अंदरूनी रास्ते और गंगा के रास्ते भी पर्यटक यहाँ आसानी से आ सकेंगे। हाइवे से सटे होने के कारण लोगों को यहाँ आने में सुविधा होगी।

नोट :

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पेश किये चार विधेयक

चर्चा में क्यों ?

10 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में उ.प्र. दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन विधेयक, 2023 समेत चार विधेयक पेश किये, जिन्हें पास भी करा लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि प्रदेश में 31 दिसंबर, 2021 तक सीआरपीसी की धारा 107 और 109 के तहत शमन शुल्क भरकर अथवा स्वत: समाप्त होने वाले मुकदमों को खत्म कर दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि पुराने प्रकरणों में अभियुक्त बार-बार समन भेजने पर उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में लंबित वादों की संख्या बढ़ती जाती है। अब अदालतों का समय बचेगा।
- उ.प्र. माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इससे छोटे कारोबारियों को ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिये व्यापार करने में सुविधा होगी। अभी तक कम टर्नओवर वाले व्यापारियों का पंजीकरण नहीं हो पाता था। इसी वजह से जीएसटी के तहत इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
- विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम से विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसकी शुरुआत 60 विद्यार्थियों से होगी। इसमें नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जारी है।
- इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- इसके साथ ही उ.प्र. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 और उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 भी पास करा लिये गए।

नोट :

स्वास्थ्य सेवाओं में ई-गवर्नेंस के लिये उत्तर प्रदेश को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

13 अगस्त, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में ई-गवर्नेंस के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने 'डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटीज'के लिये शुरू की गई परियोजना-पहल 'माँ नवजात ट्रैकिंग एप्लिकेशन'(मंत्रा) हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-उत्तर प्रदेश (एनएचएम-यूपी) को सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिये चुना है।
- ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र 24-25 अगस्त 2023 को इंदौर (म.प्र.) में प्रस्तावित ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर 26वें ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किये जाएंगे।
- एनएचएम-यूपी को यह नेशनल अवॉर्ड श्रेणी-1 के तहत 'गवर्नमेंट प्रॉसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन'के तहत ई-गवर्नेंस योजना 2023 के लिये दिया जा रहा है।
- मंत्रा ऐप को भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के लिये एक उपकरण के रूप में मान्यता दिया जाना प्रदेश के लिये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यूपी लेबर रूम के लिये ऑनलाइन एमआईएस को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य है।
- सिल्वर अवॉर्ड के तहत एनएचएम-यूपी को इस परियोजना के लिये प्रमाण-पत्र और ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक टीम सदस्यों (परियोजना प्रमुख सहित 4 लोग) को भी प्रमाण-पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी।
- स्वास्थ्य विभाग की ओर से लॉन्च किये गए मंत्रा ऐप के माध्यम से किस केंद्र पर कितना प्रसव हुआ और प्रसव संबंधी सुविधाओं की समस्त जानकारी आसानी से मिल जाती है।
- इस ऐप के माध्यम से नवजात शिशु के जन्म, टीकाकरण व प्रसव से संबंधित अन्य जानकारियों को उपचारिका एवं वार्डबाय इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े भी डिजिटल हो गए हैं। गर्भवती महिला को भर्ती करते वक्त स्टाफ नर्स द्वारा भर्ती का समय, उसके स्वास्थ्य की स्थिति और दिये जा रहे उपचार को फीड किया जाता है।
- इससे माँ और शिशु को ट्रैक करना आसान हो गया है। ऑनलाइन निगरानी होने से संस्थागत प्रसव की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और माँ-नवजात स्वास्थ्य आँकड़े भी बेहतर हुए हैं। माँ और नवजात शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रसव केंद्रों का डिजिटलीकरण भी किया गया है।

लखनऊ में बनेगा एक नया आईटी हब

चर्चा में क्यों ?

13 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य का नया आईटी हब बनाने की तैयारी शुरु करने की पुष्टि की गई है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) ने पहले ही कानपुर रोड पर अमौसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ ज़मीन पर आईटी हब स्थापित करने का खाका तैयार कर लिया है।
- आईटी हब को तीन भागों में बाँटा जाएगा, जिसमें आईटी पार्क, बिज़नेस पार्क और इंटरनेशनल इन्क्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर शामिल हैं। प्रस्तावित आईटी हब देश के सबसे बड़े आईटी हब में से एक होगा।

नोट :

- आईटी हब के ब्लूप्रिंट के मुताबिक, आईटी पार्क का निर्माण 11.47 एकड़ में किया जाना है, जबकि बिज़नेस पार्क 7.4 एकड़ में विकसित किया जाएगा। वहीं 6.9 एकड़ में इंटरनेशनल इनक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु 8.7 एकड़ भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इसके अलावा, आईटी हब में निर्मित इमारतों के बीच कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये 5.8 एकड़ में सड़कों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा।
- ब्लूप्रिंट के मुताबिक बेसमेंट और ग्राउंड समेत 6 मंज़िला इमारत में आईटी पार्क, बिज़नेस पार्क और इंटरनेशनल इनक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा।
- इन तीनों भवनों में अपनी पार्किंग सुविधा भी होगी। इनकी बेसमेंट पार्किंग में हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।
- प्रस्ताव के मुताबिक, आईटी हब को देश के एक बड़े इनक्यूबेटर के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें छह महत्त्वपूर्ण विंग शामिल होंगे, जिनमें महिला उद्यमी हब, कौशल और ज्ञान अकादमी, प्रोटोटाइपिंग सेंटर, रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल, इमर्जिंग टेक विंग और यू हब इनोवेशन हब शामिल हैं।
- इन सभी विंगों को पाँच एकड़ भूमि पर विकसित करने की योजना है। इसमें तमाम ऐसी खूबियाँ होंगी, जो लोगों को आकर्षित करेंगी।

उत्तर प्रदेश की नौ धरोहरों को मिलेगा हेरिटेज होटल का लुक

चर्चा में क्यों ?

14 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन के लिये विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने प्रदेश के नौ धरोहरों को हेरिटेज होटल का रूप देने की तैयारी शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने लखनऊ की छतर मंज़िल, कोठी गुलिस्तां-ए-इरम, कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशनुद्दौला, मीरजापुर का चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा के बरसाना जल महल, कानपुर के शुक्ला तालाब और बिठूर की टिकैतराय बारादरी को विरासत पर्यटन के लिये होटल का रूप देने की तैयारी की है।
- प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन के लिये विकसित करने की सरकार की कोशिश के क्रम में कई विख्यात होटल समूहों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है।
- इन धरोहर भवनों में निवेश के इच्छुक होटल समूहों में मुख्य रूप से लीला होटल्स, नीमराना होटल्स, इंडियन होटल्स कंपनी (ताज होटल्स), महिंद्रा होटल्स एंड रिजाट्र्स, ओबेराय होटल्स, द एमआरएस ग्रुप एंड रिजाट्र्स, ललित होटल्स, हयात रीजेंसी, सरोवर होटल्स एंड रिजाट्र्स, एकोर ग्रुप, टीएचएफ होटल्स, लैंजेर होटल्स, रॉयल आर्किड होटल्स, रमाडा होटल, क्लार्क होटल आदि शामिल हैं।
- प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन मुकेश मेश्राम के अनुसार परियोजना के लिये सफल निविदादाता का चयन गुणवत्ता और लागत प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। धरोहर भवनों के संरक्षण के लिये मापदंड और दायित्व भी तय किये गए हैं।
- इनमें पुरातात्त्विक भवन का विन्यास यथावत रखने, मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न करने, भवन का उपयोग उसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व के अनुरूप किये जाने, विरासत भवन के इतिहास के संबंध में विकासकर्ता द्वारा साईनेज की स्थापना करने, स्थानीय संस्कृति, खान-पान, कला, पोशाक, व्यंजन तथा सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन, सीएसआर के अंतर्गत चयनित विकासकर्ता द्वारा निकटवर्ती ग्रामों को अंगीकृत करते हुए उनके विकास के साथ ही 25 प्रतिशत स्थानीय नागरिकों को रोज़गार प्रदान किया जाना शामिल है।

नोट :

नोट :

नोट :

नोट :

नोट :

आगरा में इनर रिंग रोड के किनारे बनेगा विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2023 को आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि आगरा में इनर रिंग रोड स्थित एत्मादपुर मदरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 140 करोड़ रुपए की लागत से विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनेगा।

प्रमुख बिंदु

- चर्चित गौड़ ने बताया कि 7.4418 हेक्टेयर में आकार लेने वाले इस कन्वेंशन सेंटर की डीपीआर के लिये सैद्धांतिक मंज़ूरी मिल गई है। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव शहरी आवास नितिन रमेश गोकर्ण के समक्ष एडीए ने प्रजेंटेशन दिया।
- आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि एत्मादपुर मदरा में 7.4418 हेक्टेयर भूमि पर एडीए भूमि अर्जन कर चुका है। कन्वेंशन सेंटर की डीपीआर के लिये प्रस्ताव भेजा था। इसकी स्वीकृति मिल गई है। अब इसे तैयार करने की कार्ययोजना पर काम होगा।
- इस कन्वेंशन सेंटर में भव्य ऑडिटोरियम, मीटिंग व कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टेज के अलावा होटल भी होंगे, जहाँ पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ मिलेंगी।

उत्तर प्रदेश के 89 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक

चर्चा में क्यों ?

15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक (गेलेंट्री), छह पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक (डिस्टिंग्विश्ड) और 71 को सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- वीरता पदक (PMG) एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेंद्र कुमार शाही, निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह (दूसरी बार पीएमजी), मुख्य आरक्षी यशवंत सिंह (दूसरी बार पीएमजी), एडीजी मोहित अग्रवाल, एसपी विपिन टांडा, एसपी अनिल कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन सिंह, निरीक्षक राकेश सिंह, उप निरीक्षक दिनेश कुमार गौतम, आरक्षी मोहम्मद इमरान, प्रवीण कुमार, नवीन कुमार यादव को दिया गया।

नोट :

- उत्कृष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक (PPM) एडीजी ज़ोन प्रयागराज भानु भास्कर, डीआईजी ईओडब्ल्यू अखिलेश कुमार निगम, निरीक्षक मोहम्मद हाशिम, राजवीर सिंह, प्रमोद कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह को दिया गया।
- विदित है कि प्रदेश पुलिस को इस बार भी राष्ट्रपति का वीरता पदक (PPMG) नहीं मिल सका है।

उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लांच किया गया

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया के सभी महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 'चट्टानों की ज़िद पिघला दी, बाज़ू को आग बनाया है, काँधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है...' उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह एंथम सॉन्ग जारी किया है।
- इस गाने को गीतकार रितेश रजवाडा ने लिखा है जबकि कुँवर अंशिथ ने इसे गाया है। वहीं, एडिटिंग वैभव नायक ने पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम के साथ मिलकर की है।
- स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ के निवासियों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के उद्देश्य से 12 मार्च, 2021 को आरंभ हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव का 15 अगस्त, 2023 को समापन हुआ।
- इसी क्रम में खाकी के त्याग, बलिदान और तपस्या की भावना को सम्मिश्रित करने के लिये एक वर्ष के अथक परिश्रम के उपरांत उत्तर प्रदेश पुलिस का एक एंथम सॉंग बनाया गया है, जिसे 16 अगस्त को सोशल मीडिया के सभी महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया।
- 24 घंटे से भी कम समय में इसे ट्विटर पर लगभग 66 हज़ार लोगों ने देखा और 800 से अधिक लोगों ने रिट्वीट किया। साथ ही यूपी पुलिस के इस एंथम सॉन्ग को विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं केंद्रीय बलों के द्वारा भी अपने सोशल मीडिया एकाउंट से शेयर किया जा रहा है।

चार दिवसीय वाई-20 (यूथ सम्मेलन) की वराणसी में हुई शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चार दिवसीय वाई-20 (यूथ सम्मेलन) की शुरुआत हुई। 18 अगस्त को औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन का आयोजन भारत की जी-20 अध्यक्षता की रुपरेखा के तहत, युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- जी-20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि वाई-20 द्वारा चिन्हित किये गए पाँच विषयों- कार्य का भविष्य: उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह: युद्ध रहित युग का आरंभ, जलवायु परिवर्तन और

नोट :

आपदा जोखिम न्यूनीकरण: स्थिरता को जीवन शैली बनाना, साझा भविष्य: लोकतंत्र और शासन में युवा, स्वास्थ्य, कल्याण और खेल: युवाओं के लिये एजेंडा पर विचार मंथन करेंगे।

- वाई-20 शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में आरंभिक बैठक, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित 14 यूथ-20 परामर्श, लेह, लद्दाख में पूर्व शिखर सम्मेलन, विचार-मंथन सत्र, वाई-20 चौपाल और देश भर में मुख्य वाई-20 शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित किये गए विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रमों की परिणति है।
- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना, युवाओं के विकास में योगदान देना और वैश्विक मंच पर युवा एजेंडे के बारे में विचार-विमर्श करना है।
- वाई-20 शिखर सम्मेलन विभिन्न बैठकों का समापन है, जिसमें गुवाहाटी में आरंभिक बैठक, लेह, लद्दाख में पूर्व शिखर सम्मेलन और इस मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले देश भर में आयोजित विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रम शामिल हैं।
- चार दिवसीय शिखर सम्मेलन में जी-20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
- चार दिवसीय सम्मेलन में प्रमुख विशेषज्ञ, निर्णय निर्माता, जी-20 देशों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, नॉलेज पार्टनर (आईआईएम रायपुर), अकादमिक भागीदार (विश्वविद्यालय/संस्थान) एक साथ आएंगे।

उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों में खोले जाएंगे दीदी कैफे

चर्चा में क्यों ?

- 21 अगस्त, 2023 को ज़िला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 17 नगर निगम में दीदी कैफे खोले जाने हैं। इसके लिये उपयुक्त स्थान का जल्द ही चयन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- वाराणसी की तर्ज़ पर ही सरकारी कार्यालयों में खोले जाने वाले दीदी कैफे में मिलने वाली खाद्य सामग्री की कीमत कम रहेगी।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह शहर की महिलाएँ इन कैफे को चलाएंगी।
- प्रथण चरण में यह कैफे लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, झाँसी, फिरोज़ाबाद, शाहजहाँपुर और मथुरा-वृंदावन में खोले जाएंगे।
- दीदी कैफे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है तथा लोगों को उचित मूल्य पर साफ-सुथरा भोजन मिल सकेगा।
- वाराणसी में चल रही कैंटीन के अनुभव के आधार पर डूडा से प्रस्ताव तैयार कराया जाएगा। इस प्रस्ताव के आधार पर सभी निकायों में दीदी कैफे शुरू कराए जाएंगे

नोट :

उत्तर प्रदेश सरकार, कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को भी देगी मुफ्त किताबें

चर्चा में क्यों ?

- 21 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार शासन स्तर पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को भी किताबें मुफ्त में दी जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश में 2428 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को भी अब मुफ्त पुस्तकें दी जाएंगी।
- इसके लिये सरकार को अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। सरकार इन किताबों को उपलब्ध कराने के लिये 19.70 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
- देश में कई और राज्य हैं, जहाँ पर पहले से ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को यह सुविधा दी जाती है। इसमें गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु शामिल हैं। अब इस सूची में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो जाएगा

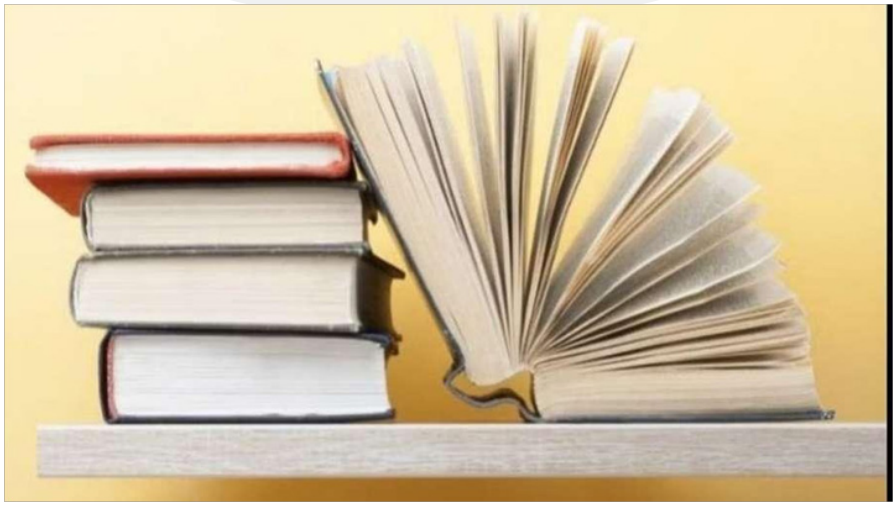

नोट :

उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त को पहली बार शाम को खुलेंगे स्कूल

चर्चा में क्यों ?

21 अगस्त, 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से मिले निर्देश के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्कूलों को 23 अगस्त को पहली बार शाम को खोलने की व्यवस्था के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि वे विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के साथ शाम 5.15 बजे से 6.15 बजे तक विशेष सभा कराएँ।
- इस दौरान चंद्रयान-3 की लैंडिंग को प्रदेश के स्कूली बच्चे टीवी या यूट्यूब चैनल पर सीधे प्रसारण के माध्यम से देखेंगे। यह भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और उद्योग के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- विदित है कि 23 अगस्त को शाम 5:27 बजे चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण ISRO Website (https://www.isro.gov.in/) एवं ISRO के आधिकारिक YouTube Channel और DD National पर किया जाएगा।

नोट :

- भारत के चंद्रयान-3 का चाँद पर उतरना एक यादगार मौका है, जो न केवल जिज्ञासा को बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं के मन में अन्वेषण के लिये एक जुनून भी जगाएगा।
- यूजीसी ने भी उच्च शिक्षण संस्थानों से ये अपील की है कि हर किसी की निगाहें चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग पर रहेंगी। इसी क्रम में यूजीसी ने चंद्रमा तक की यात्रा की जानकारी देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों को देने की अपील की है।

उच्च शिक्षा में भी 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

22 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' (उच्च शिक्षा) का विस्तार करते हुए इसमें सभी ग्रेजुएट पास युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट ने योजना के तहत प्रशिक्षुओं को निजी प्रतिष्ठानों की ओर से दिये जाने वाले स्टाइपेंड में 1000 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से किये जाने पर सहमति दी है।
- इस योजना में स्टाइपेंड की राशि को भी बढ़ाकर प्रतिमाह 9 हज़ार रुपए किया गया है। इसमें राज्य सरकार की ओर से एक हज़ार रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जबकि बाकी राशि केंद्र सरकार एवं एंटप्रेन्योर्स द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस राशि में 50 फीसदी, यानी 4500 रुपए भारत सरकार व 50 फीसदी संबंधित 3500 रुपए संस्थान देते हैं। अब संस्थान की ओर से दी जाने वाली राशि में अतिरिक्त 1000 रुपए प्रदेश सरकार देगी।
- शासन ने 2023-24 में इसके लिये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है तथा शिक्षा विभाग को इसके लिये नोडल विभाग बनाया गया है।
- प्रस्तावित योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के संस्थानों को अधिक-से-अधिक गैर-तकनीकी डिप्लोमा होल्डर एवं डिग्री होल्डर युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- योजना के तहत प्रदेश के गैर-तकनीकी डिप्लोमा होल्डर्स तथा ग्रेजुएट युवाओं को एक वर्ष का रोज़गार प्राप्त होगा, जबकि निजी, शासकीय संस्थानों को कुशल कार्मिक मिलेंगे।

नोट :

गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ी हुए सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

21 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में आयोजित दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियो को उत्तर प्रदेश 'केसरी', उत्तर प्रदेश 'कुमार'व उत्तर प्रदेश 'वीर अभिमन्यु'पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के खेल प्रेमियों के साथ मिलकर इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया और सामूहिक भागीदारी से इसे रोचक बनाया।
- उत्तर प्रदेश 'केसरी'पुरस्कार विजेता जोंटी को 01 लाख 01 हज़ार रुपए व गदा तथा उप विजेता वीरेश कुंडू को 51 हज़ार रुपए प्रदान किये गए।

नोट :

- उत्तर प्रदेश 'कुमार'पुरस्कार विजेता सौरभ यादव को 51 हज़ार रुपए व गदा तथा उप विजेता बघेल यादव को 25 हज़ार रुपए प्रदान किये गए।
- उत्तर प्रदेश 'वीर अभिमन्यु'पुरस्कार जीतने वाले आदित्य यादव को 51 हज़ार रुपए व गदा तथा उप विजेता विनीत को 25 हज़ार रुपए प्रदान किये गए।
- इनके अलावा वॉलीबॉल खिलाड़ी युवराज प्रताप सिंह, कुश्ती के सौरभ यादव व टेनिस बॉल के खिलाड़ी अमन राज को भी सम्मानित किया गया।
- केंद्र व राज्य सरकार ने खेलों तथा खिलाड़ियों के लिये 'खेलो इंडिया'और 'सांसद खेल महाकुंभ' जैसे खेल आयोजनों के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया है।

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2023

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2023 का आयोजन कर रही है, जो ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 21 से 25 सितंबर, 2023 के बीच होगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2023 के तहत 21 से 25 सितंबर तक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, साथ ही सेमिनार और सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होंगी।
- ट्रेड शो में अच्छा व्यापार करने वाले उत्पादकों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदर्शनी में अलग-अलग सेक्टरों से जुड़े 2000 से अधिक उत्पादक और निर्यातक भाग लेंगे।
- इंडिया एक्सपो मार्ट के 15 हॉल में करीब 50 हज़ार वर्गमीटर में लगने वाली प्रदर्शनी में एक जनपद, एक उत्पाद जैसे बनारस की गुलाबी मीनाकारी व सिल्क, बांदा का सजर स्टोन, कन्नौज के इत्र, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का ब्रास वेयर और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी भी प्रदर्शित की जाएगी।
- ट्रेड शो में लोगों का प्रवेश नि:शुल्क होगा, ताकि आम जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो सके।
- सरकार ने ज़िला स्तर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन को आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है।
- पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिये स्कूल, कॉलेज, आरडब्ल्यूए, एओए और उद्यमियों का सहयोग लिया जाएगा।

नोट :

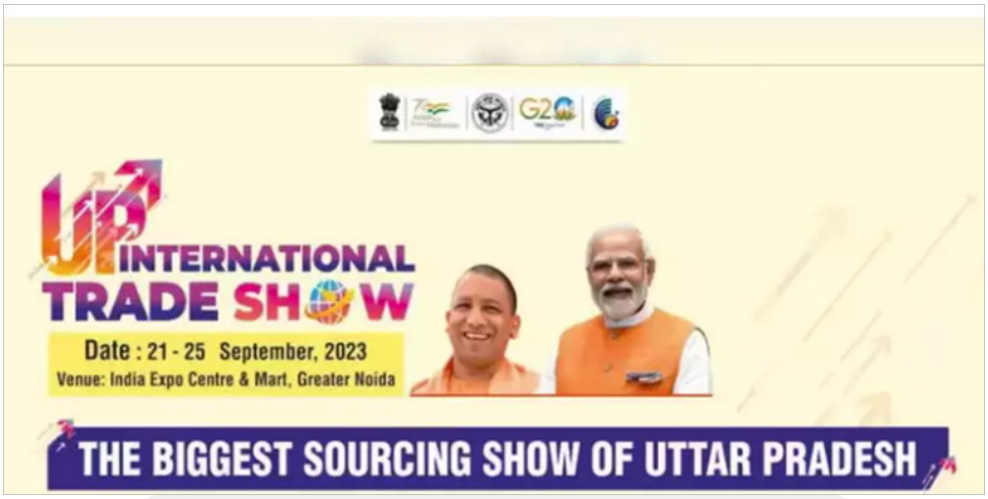

भारत की अध्यक्षता में जी20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न

चर्चा में क्यों ?

26 अगस्त, 2023 को भारत की अध्यक्षता में जी20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जी20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के संस्कृति मंत्रियों एवं गण्यमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में, भारत की अध्यक्षता में जी20 संस्कृति कार्य समूह भारत के सीडब्ल्यूजी द्वारा व्यक्त चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये ठोस कार्य-उन्मुख परिणामों को आकार देने में लगा हुआ है।
- यह चर्चा सीडब्ल्यूजी बैठकों, द्विपक्षीय सत्रों और वैश्विक विषयगत वेबिनार की एक श्रृंखला द्वारा निरंतर विचार-विमर्श के माध्यम से की जा रही है। संस्कृति मंत्रियों की बैठक (सीएमएम) पिछली बैठकों की सभी चर्चाओं, विचार-विमर्श और पहलों का निचोड़ थी।
- जी20 संस्कृति मंत्रियों ने आज की बहुआयामी विकास चुनौतियों, जैसे- जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानताओं और दूसरों के बीच डिजिटल परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने के लिये संस्कृति की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की और अधिक समावेशी समाजों को आकार देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो सभी संस्कृतियों की विविधता और समान गरिमा की मान्यता के पूर्ण सम्मान पर आधारित हैं।
- भारत के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम के दस्तावेज़ को 'काशी संस्कृति मार्ग'का नाम दिया गया है। यह भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत जी20 संस्कृति कार्य समूह द्वारा व्यक्त प्राथमिकताओं पर जी20 संस्कृति मंत्रियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं और आम सहमति का सारांश प्रस्तुत करता है।
- जी20 एमओसी ने सर्वसम्मति से काशी संस्कृति मार्ग नामक परिणाम दस्तावेज़ को अपनाया है।
- जी20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के दौरान जी20 संस्कृति मंत्रियों द्वारा रिपोर्ट 'जी20 कल्चर: शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ'को लॉन्च किया गया। इसमें मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान आयोजित भारतीय अध्यक्षता द्वारा व्यक्त की गई चार प्राथमिकताओं पर विशेषज्ञ-संचालित वैश्विक विषयगत वेबिनार की अंतर्दृष्टि और सिफारिशें शामिल हैं। यह सारगर्भित प्रकाशन भारत की जी20 अध्यक्षता में आयोजित वैश्विक विषयगत वेबिनार की कार्यवाही का डॉक्युमेंटेशन करता है।
- संस्कृति मंत्रियों ने एक विशेष संस्करण डाक टिकट जारी किया। यह विशेष डाक टिकट हॉलमार्क अभियान 'कल्चर यूनाइट्स ऑल'की स्मृति में लॉन्च किया गया था, जो भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत संस्कृति कार्य समूह की एक पहल थी। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान, 'संस्कृति सभी को एकजुट करती है'अभियान समावेशी विकास के लिये बहुपक्षवाद में भारत के अटूट विश्वास के प्रमाण के रूप में खड़ा रहा।

नोट :

- इसके बाद, संस्कृति मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भारत के जी20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह द्वारा आयोजित जी20 ऑर्केस्ट्रा- 'सुर वसुधा'देखा। 'सुर वसुधा'या धुनों का खजाना जी20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के समृद्ध संगीत ज्ञान एवं विरासत का जश्न मनाता है।
- 'वसुधैव कुटुंबकम' या 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'की भावना में, संगीत कार्यक्रम में जी20 सदस्य और अतिथि देशों के संगीत एवं संगीत वाद्ययंत्रों को शामिल किया गया। संगीतकारों के लिये इस साझा मंच का उद्देश्य समावेश और विविधता को बढ़ावा देना एवं संगीत के माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- संस्कृति मंत्रियों की बैठक के महत्त्वपूर्ण नतीजे उन महत्त्वाकांक्षी और सामूहिक कार्रवाइयों में शामिल होंगे, जिन पर जी20 लीडर्स सितंबर 2023 में जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा करेंगे।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झाँसी में लोकार्पण किया। साथ ही यहाँ पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ हॉकी ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया तथा खेल दिवस पर होने वाले हॉकी मैच का शुभारंभ किया।
- हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 19 करोड़ रुपए की लागत से मेयर ध्यानचंद म्यूजियम बनाया गया है।
- हॉकी को समर्पित यह देश का पहला म्यूजियम है। इसमें मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ी स्मृतियाँ, घटनाएँ एवं भारतीय हॉकी की विभिन्न जानकारियाँ डिजिटल माध्यम से दिखाई जाएंगी।
- इसको 20 से अधिक ज़ोन में बाँटा गया है, जिसका प्रत्येक ज़ोन अपने आपमें अलग और अद्भुत है। यह जनता के लिये एक सितंबर से खोला जाएगा।

नोट :

सीकरी की वर्षा को मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

30 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में तैनात वर्षा चाहर को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार, 2022 के लिये चुना गया है। उन्होंने अपने अथक् प्रयासों से विद्यालय को नई पहचान दिलाई है।

प्रमुख बिंदु

- आगरा की वर्षा चाहर फतेहपुर सीकरी ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दाउदपुर की हेड हैं।
- करीब 4 वर्ष पूर्व 2019 में, जब वर्षा इस विद्यालय में आई थीं, तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षिक स्तर सामान्य से भी नीचे था, लेकिन अपने अथक् प्रयासों से वर्षा ने न केवल विद्यालय, बल्कि स्कूल के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के स्तर में भी सुधार किया है।
- उनके प्रयासों से दाउदपुर का यह छोटा-सा, विद्यालय न केवल 'मेरा विद्यालय मेरी पहचान' जनपदस्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है, बल्कि तमाम प्रतियोगिता में वर्षा खुद और उनके विद्यालय के बच्चे चयनित होकर आगरा का नाम रोशन कर रहे हैं।
- विद्यालय की उपलब्धियाँ-
  - 'मेरा विद्यालय मेरी पहचान' जनपद स्तर में प्रथम (उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार)
  - राज्यस्तरीय पर्यावरण अर्थियन पुरस्कार, 2023
  - नेशनल मींस-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में 2022 में 2 बच्चे तथा 2023 में 5 बच्चे चयनित हुए।
  - श्रेष्ठा योजना में 5 बच्चों का चयन, जिनमें से 2 बच्चों को डीपीएस स्कूल मिल चुका है।
  - जनपदस्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान आविष्कार प्रतियोगिता में 2022 तथा 2023 में विद्यालय के छात्रों का चयन।
- वर्षा चाहर की उपलब्धियाँ-
  - राज्यस्तरीय अर्थियन पर्यावरण पुरस्कार, 2023 से सम्मानित।
  - जनपदस्तरीय कला क्राफ्ट पपेट्री प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चयनित।
  - जनपदस्तरीय षष्ठम् कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में प्रथम।
  - जनपदस्तरीय उत्कृष्ट अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित।

नोट :